उच्च शिक्षा की प्रवृत्तियाँ एवं चुनौतियाँ

निशात फ़ात्मा*

किसी देश का विकास उस देश की शिक्षा प्रणाली पर निर्भर करता है, क्योंकि देश की उन्नति के लिए हर व्यक्ति ज़िम्मेदार है और वह ही देश को अपने ज्ञान, संस्कार और अच्छे आचरण के बल पर समृद्धि की ओर ले जा सकता है। आज का शिक्षित वर्ग ही देश की अर्थव्यवस्था को सुचारु रूप से चला सकता है, किंतु अगर शिक्षा प्रणाली ही ठीक न हुई तो उस देश का भविष्य अंधकारमय हो सकता है। इसलिए आज आवश्यकता है एक ऐसी शिक्षा प्रणाली की जिससे व्यक्ति में ज्ञान के साथ-साथ अच्छे आचरण का भी विकास हो सके, वह भावनात्मक रूप से सुरक्षित महसूस कर सके, रोज़गार के अवसर प्राप्त कर सके और उसकी रचनात्मकता की अभिव्यक्ति के लिए भी पर्याप्त अवसर उपलब्ध हों। 'मेक इन इंडिया' और 'डिजिटल इंडिया' जैसी योजनाओं को सफल बनाने के लिए हमारे विद्यार्थियों को उच्च गुणवत्ता वाली शिक्षा की आवश्यकता है।

'शिक्षा' शब्द मोटे तौर पर दो रूपों में प्रयोग में लाया जाता है — व्यापक रूप में तथा संकुचित रूप में। व्यापक रूप में शिक्षा किसी समाज में सदैव चलने वाली सोद्देश्य सामाजिक प्रक्रिया है, जिसके द्वारा मुनष्य की जन्मजात शक्तियों का विकास, उसके ज्ञान एवं कौशल में वृद्धि एवं व्यवहार में परिवर्तन किया जाता है और इस प्रकार उसे सभ्य, सुसंस्कृत एवं योग्य नागरिक बनाया जाता है। स्वतंत्रता के बाद शिक्षा प्रणाली की क्या उपलब्धि है, यदि हम इस ओर ध्यान दें तो संभवतः हमें कुछ संतोषजनक आँकड़े मिलेंगे। आज हमारे देश में तकरीबन 10 लाख स्कूलों में 2025 लाख बच्चों को पढ़ाने का काम लगभग 55 लाख शिक्षक कर रहे हैं। 82 प्रतिशत रिहायशी इलाकों में एक किलोमीटर की परिधि के अंदर प्राथमिक और 75 प्रतिशत रिहायशी इलाकों में तीन किलोमीटर के दायरे में उच्च प्राथमिक पाठशालाएँ हैं। माध्यमिक स्तर की परीक्षा में भाग लेने वाले विद्यार्थियों में कम से कम 50 प्रतिशत विद्यार्थी परीक्षा में उत्तीर्ण होते हैं। इन आँकड़ों के बावजूद भारत के 37 प्रतिशत लोगों में साक्षरता कौशलों का अभाव है। प्राथमिक स्कूलों में विद्यार्थियों के स्कूल छोड़ने की दर 53 प्रतिशत है और उच्च शिक्षा हेतु पंजीकरण कराने वाले विद्यार्थियों का अनुपात भारत में विश्व में सबसे

**पी.जी.टी.* हिंदी, जामिया सीनियर सेकंडरी स्कूल, जामिया मिल्लिया इस्लामिया, नयी दिल्ली – 110 025

कम यानी 11 प्रतिशत है, जबकि अमेरिका में यह 83 प्रतिशत है। 11वीं पंचवर्षीय योजना में शिक्षा के लिए अनुमानित राशि ₹12,44,797 करोड़ का ही प्रावधान किया गया था।

जिस समय दुनिया ने विद्यालयों की कल्पना भी नहीं की थी, उस समय भारत में विश्वविद्यालय हुआ करते थे। विश्व स्तरीय नालंदा विश्वविद्यालय, तक्षशिला विश्वविद्यालय और विक्रमशिला विश्वविद्यालय की पावन धरती पर शिक्षा व्यवस्था की यह विसंगतियाँ कहीं-न-कहीं मन को आहत करती हैं। आज चारों तरफ़ अनास्था का माहौल पनप रहा है। गुरु-शिष्य संबंध का घनत्व घट रहा है। उच्च शिक्षा की स्थिति दिन पर दिन खराब होती जा रही है। शिक्षा पर सकल घरेलू उत्पाद का जितना प्रतिशत खर्च होना चाहिए, वह नहीं हो रहा है। रक्षा और अन्य मंत्रालयों का बजट लंबा-चौड़ा होता है पर शिक्षा की अनदेखी होती है। समय पर कार्यों के पूर्ण न होने के कारण हड़ताली प्रवृत्ति विकसित होती जा रही है, जिसका परिणाम अंतत: विद्यार्थियों को ही भुगतना पड़ता है। अतः हमें व्यवस्थागत मुद्दों पर ध्यान देने व उन्हें नियोजित करने की आवश्यकता है ताकि हम उन अनेक अच्छे विचारों को कार्यान्वित कर सकें जिनके बारे में पहले भी चर्चा की जा चुकी है, यथा —

- ज्ञान को स्कूल के बाहर के जीवन से जोड़ना।
- सुनिश्चित करना कि पढ़ाई रटंत प्रणाली से मुक्त हो।
- पाठ्यचर्या का इस तरह संवर्धन करना कि वह पाठ्यपुस्तक केन्द्रित न बनकर बच्चों को चहुँमुखी विकास के अवसर उपलब्ध कराए।
- परीक्षा को अपेक्षाकृत अधिक लचीला बनाना और कक्षा की गतिविधियों से जोड़ना।
- एक ऐसी अधिभावी पहचान का विकास, जिसमें प्रजातांत्रिक राज्य व्यवस्था के अन्तर्गत राष्ट्रीय चिंताएँ समाहित हों।

उच्च शिक्षा में सुधार हेतु 1986 में रोज़गारोन्मुखी नई शिक्षा नीति भी लाई गई, किन्तु उसका क्रियान्वयन प्रभावी रूप से नहीं हुआ और आज भी हम मूल्यपरक शिक्षा नीति की बाट जोह रहे हैं। नैसकॉम और मैकिन्से के ताज़ा शोध के मुताबिक मानविकी में 10 में एक और अभियंत्रण में डिग्री प्राप्त चार में से एक भारतीय विद्यार्थी ही नौकरी पाने योग्य है। राष्ट्रीय मूल्यांकन व प्रत्यापन परिषद् (नैक) का शोध बताता है कि इस देश के 90 फ़ीसदी कॉलेजों एवं 70 फ़ीसदी विश्वविद्यालयों का स्तर बेहद कमज़ोर है। स्वतंत्रता के बाद 50 सालों में 44 निजी संस्थानों को डीम्ड विश्वविद्यालयों का दर्जा मिला। पिछले 16 वर्षों में 69 और निजी विश्वविद्यालयों को मान्यता दी गई। शिक्षा के वैश्वीकरण के इस दौर में महँगे कोचिंग संस्थान, किताबों की बढ़ती कीमत, डीम्ड विश्वविद्यालय और विद्यार्थियों में सिर्फ़ सरकारी नौकरी पाने की एक आम अवधारणा का पनपना आज की उच्च शिक्षा की अहम चुनौतियाँ हैं।

इस उपभोगतावादी संस्कृति ने हमें 'स्व' से अलग कर दिया है। इस शिक्षा पद्धति का शरीर तो सक्षम है, पर आत्मा कमज़ोर है। इस रुग्ण आत्मा की कमज़ोरी को दूर करना होगा। युवा पीढ़ी के अंदर की बेचैनी व छटपटाहट को समझते-परखते हुए उसे

भटकाव से रोकना होगा। मन-मस्तिष्क और हाथों के सुंदर समन्वय से पूर्ण मनुष्य के निर्माण की प्रक्रिया का द्वार खोलना होगा। हमें गुणात्मक शिक्षा को अपनाना होगा, जिसमें नैतिकता का पुट हो।

सम्प्रति भारत में जो शिक्षा पद्धति प्रचलित है, उसके कई पक्षों में सुधार की आवश्यकता है। हमारी शिक्षा व्यवस्था पर एक वृहद् जनसमूह को शिक्षित करने का उत्तरदायित्व है, परंतु साधन और संसाधन बहुत सीमित हैं, परिस्थितियाँ भी अनुकूल नहीं, फिर भी हम लक्ष्यों की प्राप्ति की ओर प्रयत्नशील रहें और दृढ़ संकल्प के साथ आगे बढ़ें तो इस निराशाजनक स्थिति से उबर सकते हैं। अगर कुछ चुनौतियों की बात करें तो ऐसी शिक्षा की व्यवस्था करनी होगी, जो व्यक्ति को समाज में स्थान दिला सके। आज औद्योगिक क्रांति के कारण नए भारतीय समाज का निर्माण हो रहा है जिसमें कई शाश्वत मूल्यों का धीरे-धीरे लोप होता जा रहा है। भौतिक सम्पन्नता तो आई है, परंतु नैतिक मूल्यों का ह्रास हो गया है या वास्तव में, हम शिक्षा के मूल मर्म से दूर हो गए हैं। शिक्षा की प्रासंगिकता की बात की जाए तो उच्च शिक्षा में व्यावसायिकता इतनी हावी होती जा रही है कि लैंगिक भेदभाव, महिलाओं के प्रति हिंसा, स्वास्थ्य, सुरक्षा जैसे मुद्दे अनावश्यक लगते हैं। अंकों की दौड़ में चाहे-अनचाहे व्यक्तित्व विकास की बहुत-सी समस्याएँ अनसुलझी रह जाती हैं, जोकि भविष्य में निराशा, हताशा और कुंठा के रूप में अपराधी वृत्तियों को जन्म देती हैं। वर्तमान शिक्षा का उद्देश्य कुछ परीक्षाएँ उत्तीर्ण कर नौकरी प्राप्त करना है और अगर दुर्भाग्यवश शिक्षा प्राप्त करके भी नौकरी न मिले तो...। इस भय से दूर क्या यह शिक्षा व्यक्ति को यह स्वतंत्रता देती है कि वह नौकरी न मिलने पर भी स्वरोज़गार से अपने जीवन को सफल बना सकता है। यह एक गंभीर समस्या है जो हमारी शिक्षा को अर्थहीन बनाती है। आने वाले समय में शिक्षा की परिभाषा में व्यापक परिवर्तन करने होंगे जिससे शिक्षा उपयोगी और लक्ष्य आधारित हो।

सबसे बड़ी त्रासद स्थिति यह है कि विश्व के शीर्ष 200 विश्वविद्यालयों की सूची में भारत का कोई विश्वविद्यालय नहीं है, अर्थात् विश्व को भारत की उच्च शिक्षा ने प्रभावित नहीं किया है। देश में साक्षरता दर तो बढ़ी है, लेकिन हम गुणवत्ता नहीं बढ़ा पाए हैं। यहाँ कक्षाओं में केवल किताबी ज्ञान मिलता है जबकि आज व्यावहारिक ज्ञान की आवश्यकता अधिक महसूस की जा रही है। देश में वैज्ञानिक शोध और अनुसंधान की दशा विचारणीय है और हमारे विश्वविद्यालय एम.फ़िल और पीएच.डी की सिर्फ़ डिग्री बाँट रहे हैं। कई विश्वविद्यालयों में तो धन लेकर डिग्री देने का खुला खेल चल रहा है। रही-सही कसर स्व-वित्तपोषित विश्वविद्यालयों और महाविद्यालयों ने पूरी कर दी है, जहाँ शिक्षकों की कमी है और जो हैं भी, उनकी स्थिति दयनीय है। उनकी नियुक्ति प्रक्रिया में अनेक विसंगतियाँ हैं। महाविद्यालयों में कई तरह के शिक्षक कार्यरत हैं, जिनकी नियुक्ति प्रक्रिया के मापदंड भी अलग-अलग हैं। यही नहीं स्व-वित्तपोषित महाविद्यालयों में अत्यंत अव्यवस्था है। इनमें मनमानी फ़ीस वसूल कर विद्यार्थियों का तो शोषण किया ही जाता है, साथ ही शिक्षकों के लिए बुनियादी सुविधाओं का भी अभाव है। अधिकांश महाविद्यालयों में योग्य शिक्षकों का अनुमोदन करा लिया जाता है, किंतु उनसे पढ़वाया नहीं जाता। जहाँ

पढ़वाया जाता है, वहाँ उन्हें ₹8000 से ₹15000 तक के अल्प वेतन पर रखा जाता है, जिससे उनका मनोबल गिर जाता है। वे अपने जीवन की समस्याओं में ही उलझे रहते हैं। उन्हें अगले वर्ष नौकरी पर रखा जाएगा या नहीं, इस बात की भी कोई गारंटी नहीं होती। प्रबंधक की जी-हुज़ूरी पर नौकरी टिकी होती है। जिस दिन प्रबन्धक ने न कहा, उस दिन नौकरी से बाहर। ऐसी स्थिति को सुधारने के लिए सरकार को भर्ती प्रक्रिया आरंभ कर शिक्षकों की कमी को दूर करना होगा तथा निजी महाविद्यालयों में विश्वविद्यालयों की ओर से वेतन निर्धारण कर शिक्षकों की स्थिति में सुधार करना होगा। विश्वविद्यालयों तथा महाविद्यालयों को यू.जी.सी. के मानक नैक (एन.ए.ए.सी.) का पालन करने के लिए बाध्य किया जाए ताकि शिक्षण संस्थानों की हालत में सुधार हो। सरकार को उच्च शिक्षा संस्थानों की संख्या बढ़ाने के साथ-साथ उसकी गुणवत्ता को भी श्रेष्ठ स्तर पर लाना होगा। देश की उच्च शिक्षा को मूलभूत संकल्पना के साथ आधुनिक आवश्यकताओं के अनुसार ढालना होगा। इस हेतु इसके अनुरूप पाठ्यचर्या एवं पाठ्यक्रम की रचना करनी होगी, शोध कार्यों को बढ़ावा देना होगा, शिक्षा की गुणवत्ता बढ़ानी होगी तथा देश की उच्च शिक्षा मूल्य आधारित बने इसलिए शिक्षा में स्वायत्तता होनी चाहिए। उच्च शिक्षा के द्वारा आर्थिक व्यवस्था में सुधार हो, ऐसी शिक्षा का प्रारूप तैयार करना होगा।

पढ़ाई बीच में छोड़ने वाले बच्चों के लिए दो प्रकार के पाठ्यक्रमों की व्यवस्था करनी होगी और इन बच्चों को दोनों में से किसी एक पाठ्यक्रम को चुनने की स्वतंत्रता होनी चाहिए। पहले पाठ्यक्रम के अंतर्गत स्थानीय व्यावसायिक संस्थानों द्वारा दो वर्षीय कौशल प्रशिक्षण कार्यक्रम सम्मिलित करना होगा। दूसरे पाठ्यक्रम के अंतर्गत विद्यार्थियों को विज्ञान और मानविकी विषयों में शिक्षा देने के लिए एक तीन वर्षीय पाठ्यक्रम में शामिल करना होगा। इन दोनों पाठ्यक्रमों में से शीर्ष 10 प्रतिशत विद्यार्थियों को अनिवार्य परीक्षा उत्तीर्ण करने के बाद देश के उच्च शिक्षण संस्थानों में प्रवेश की इजाज़त मिलनी चाहिए। इस प्रकार पढ़ाई पूरी न करने वाले लोगों को न केवल शिक्षा दी जा सकती है, बल्कि उनके लिए रोज़गार भी सुनिश्चित कराया जा सकता है।

निष्कर्षत: यह कहा जा सकता है कि इक्कीसवीं सदी के शुरुआती दौर में भारत की शिक्षित युवा पीढ़ी ने सूचना और संचार तकनीक के क्षेत्र में उसे अत्यंत सम्मानजनक स्थान दिलाया है। नई कार्य संस्कृति के अंतर्गत भारत की वैज्ञानिक तथा तकनीकी क्षेत्र की क्षमताओं को अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भरपूर सराहना मिल रही है, लेकिन उच्च शिक्षा के संबंध में चिंताजनक आँकड़े हमारी प्रगति पर पानी फेरते हुए दिखाई दे रहे हैं।

उच्च शिक्षा में सुधार के लिए सरकार को न सिर्फ़ उच्च शिक्षण संस्थानों की संख्या बढ़ानी होगी, बल्कि उसकी गुणवत्ता को भी श्रेष्ठ स्तर पर लाना होगा। देखने वाली बात यह है कि देश में सर्वोच्च गुणवत्ता वाले शैक्षणिक संस्थान कहाँ तक सफलता प्राप्त कर पाते हैं। एक तरफ़ सरकार शिक्षा में सुधार की योजनाएँ बनाने में दिलचस्पी दिखाती है, तो दूसरी ओर योजनाओं के सही क्रियान्वयन की ओर कोई सकारात्मक पहल नहीं की जाती है। इससे यह

स्पष्ट हो जाता है कि शिक्षा में किए जा रहे भेदभाव को समाप्त करने की दिशा में कदम बढ़ाएँ तो शिक्षा की गुणवत्ता कायम हो सकती है। *एनडीटीवी इंडिया* के अनुसार देश के विश्वविद्यालयों और महाविद्यालयों की जो भयावह स्थिति सामने आ रही है, उसमें सुधार की बहुत आवश्यकता है। यह तभी संभव है जब राज्य सरकारें नींद से जागकर बेरोज़गारों के लिए नौकरी की व्यवस्था करें। परीक्षाफल समय पर जारी करें और नियुक्त होने वाले उम्मीदवारों को समय पर नियुक्ति पत्र जारी करें। सरकारों के बदलने का प्रभाव किसी भी प्रतियोगी परीक्षा पर न पड़े। जो प्रक्रिया चल रही है, वह आगे बढ़ती रहे, ऐसा न हो कि सरकार बदलते ही भर्ती प्रक्रिया पर रोक लगा दी जाए और नयी व्यवस्था आरंभ कर दी जाए। ऐसा करने से विद्यार्थियों का धन और समय, दोनों ही बर्बाद होता है। एक तथ्य यह भी है कि 21वीं सदी की उच्च शिक्षा को तब तक स्तरीय नहीं बनाया जा सकता, जब तक कि भारत की स्कूली शिक्षा 19वीं सदी में विचरण करती रहेगी। स्कूली शिक्षा की मूलभूत सुविधाओं में पिछले दशक में वृद्धि हुई है, लेकिन वहाँ भी समस्या गुणवत्ता की है। भारत के आधे से अधिक प्राथमिक विद्यालयों में कोई भी तकनीकी गतिविधि नहीं होती, जिससे भारतीय बचपन सूचना और तकनीकी के युग में भी बहुत पिछड़ा हुआ है। अब समय आ गया है कि चॉक और ब्लैक-बोर्ड के साथ-साथ शिक्षा के लिए तकनीक का प्रयोग किया जाए। सरकारी विद्यालयों में 'स्मार्ट' कक्षाओं की व्यवस्था हो, ताकि उच्च कक्षाओं तक पहुँचते-पहुँचते विद्यार्थी आधुनिक तकनीक में पूर्ण-रूप से पारंगत हो जाएँ। नयी सोच, नई विचारधारा और नए परिवेश का उच्च शिक्षा में संचार हो सके। गुणवत्ता में सुधार के लिए तुरंत एक्शन प्लान की आवश्यकता है। पुस्तकालय, शोध पत्रों, शोध-शोधकों की संख्या में वृद्धि करनी होगी और विश्वविद्यालयों की संख्या बढ़ाने के साथ-साथ गुणवत्ता में वृद्धि और मूल्यांकन में सुधार करना होगा।

वास्तव में, अगर देश को 2020 तक सुपर पावर बनाना है तो उसके लिए पढ़े-लिखे तथा दक्ष कर्मियों की बड़ी संख्या में ज़रूरत होगी और इसके लिए उच्च शिक्षा के क्षेत्र में सख्त परिवर्तन करने होंगे। सरकार इस बारे में ध्यान दे रही है, जोकि एक उत्तम संकेत है। देश और समाज चाहता है कि उच्च शिक्षा नीतियों में जल्द बुनियादी बदलाव लाकर इन्हें क्रियान्वित किया जाए ताकि देश के शैक्षणिक विकास का मानचित्र गौरवशाली बना रहे। ये सभी सुझाव उच्च शिक्षा की चुनौतियाँ और मुद्दे हैं जो सभी के सहयोग और भागीदारी से पूर्ण किए जा सकते हैं।

संदर्भ

जिज्ञासु, जयंत. 2014.'भारतीय उच्च शिक्षा की चुनौतियाँ.' https://readerblogs.navbharattimes.indiatimes.com/ANCHHUA-KONA/जयन-त-ज-ज-ञ-स8/ से लिया गया.

नंदा, प्रशांत के. 06 सितम्बर, 2017. *द वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग्स 2018 — आई.आई.एस.सी. स्लाइड्स, नो इंडियन इंस्टीट्यूट इन टॉप 200*. https://www.livemint.com/Education/EtUBYaH5PAde3y1u325PKO/THE-World-University-Rankings-2018-IISC-slides-no-Indian-i.html से लिया गया.

राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान और प्रशिक्षण परिषद्. 2006. *राष्ट्रीय पाठ्यचर्या की रूपरेखा 2005*. रा.शै.अ.प्र.प., नयी दिल्ली.

सिंह, प्रणय विक्रम. 2009. *शिक्षा व्यवस्था के सुधार के लिए आवश्यक है धन से अधिक धुन*. https://hindi.yourstory.com/read/db0e466639/more-than-money-is-nee से लिया गया.